Title: Need to enhance the quota of foodgrains to Uttaranchal under New Public Distribution System. -Laid

श्री बची सिंह रावत ठबचदा'(अल्मोड़ा): सभापति महोदय, पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के कारण उ.प्र. के पर्वतीय (उत्तरांचल) क्षेत्र में खाद्यान्न का भीषण संकट चल रहा है। यह नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू की गई है जिसके कारण अब पूरे देश में प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह दस किलो राशन दिया जा रहा है। दिनांक १-६-९७ को नई खाद्यान्न नीति लागू करने से पहले उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गमता, वहां पर खाद्यान्न की उपज न होने के बराबर होने तथा खाद्यान्न का नियमित बाजार न होने एवं खुले बाजार की दुकान न होने के कारण उत्तरांचल के ८९ विकास खंड़ों में आर.पी.डी.एस. प्रणाली लागू थी जिसके तहत एक राशनकार्ड पर प्रतिमाह ४०-४५ किलो राशन मिल जाता था। मेरे द्वारा ११वीं लोक सभा में इस विषय को उठाने के बावजूद भी पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री ने दिनांक २१-६-९७ को उत्तरांचल क्षेत्र के पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में घोषणा की थी कि उत्तरांचल क्षेत्र का खाद्यान्य संकट तीन दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा। किन्तु उत्तरांचल क्षेत्र के खाद्यान्न कोटे में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उत्तरांचल क्षेत्र में आर.पी.डी.एस. प्रणाली लागू कर खाद्यान्न की मात्रा में शीघ्र वृद्धि की जाए तथा गरीब जनता को भुखमरी से बचाया जाए।